

बंदी सिंहों की रिहाई की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहा कौमी इंसाफ मोर्चा का धरना

चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर लगातार प्रदर्शन: कानून-त्यवस्था व ट्रैफिक पर दबाव

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

चंडीगढ़-मोहाली सीमा एक बार फिर कानून-व्यवस्था और राजनीतिक-सामाजिक तनाव का केंद्र बन गई है। कौमी इंसाफ मोर्चा के समर्थकों और पुलिस के बीच स्वतंत्रता दिवस पर हुए टकराव के बाद अब इस मुद्दे का असर केवल प्रदर्शन स्थल तक सीमित नहीं रहा। सीमा पर भारी सुरक्षा, रास्तों की बंदिश और प्रदर्शनकारियों के चंडीगढ़ की ओर बढ़ने के प्रयासों से ट्राईसिटी में यातायात प्रभावित हुआ है।

दूसरी ओर, मोर्चे ने अपने आंदोलन को और तेज करने का संकेत देते हुए 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया है। मामला मूल रूप से उन सिख बंदियों की रिहाई से जुड़ा है, जिन्हें मोर्चा 'बंदी सिंह' कहता है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कई बंदी अपनी निर्धारित सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जेलों में हैं। मोर्चा लंबे समय से उनकी रिहाई, पैरोल और संबंधित मामलों में सरकारों से निर्णय की मांग करता रहा है। इसी मुद्दे को लेकर सात जनवरी 2023 से मोहाली में वाईपीएस चौक के पास धरना जारी है। तीन साल से अधिक समय से चल रहे इस धरने ने चंडीगढ़-मोहाली सीमा को आंदोलन के स्थायी केंद्र में बदल दिया है।

स्वतंत्रता दिवस पर मोर्चे ने पंजाब के राज्यपाल के आवास यानी लोकभवन की ओर मार्च का आह्वान किया था। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर कई स्तरों पर बैरिकेडिंग की और प्रदर्शनकारियों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने पहले बातचीत और रोकने के प्रयास किए। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे और बैरिकेड हटाने का प्रयास हुआ तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टरों की मदद से बैरिकेड हटाने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया।

घटना के दौरान पथराव और धक्का-मुक्की के आरोप भी सामने आए। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से ने बैरिकेड पार करने और सुरक्षा बलों से भिड़ने की कोशिश की। दूसरी ओर, मोर्चे से जुड़े लोगों का आरोप है कि वे अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे और पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। दोनों पक्षों के दावों में अंतर को देखते हुए घटनाक्रम की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से ही पूरी तस्वीर साफ हो सकती है।

शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, आम नागरिकों की आवाजाही को सुरक्षित रखना जरूरी: पुलिस

पुलिस के सामने मुख्य चुनौती प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकने के साथ-साथ शहर में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों और आम नागरिकों की आवाजाही को सुरक्षित रखना था। प्रशासन ने प्रदर्शन के मद्देनजर शहर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए थे। रिपोर्टों के अनुसार, सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 3,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। सीमा के अलावा संवेदनशील स्थानों और प्रमुख मार्गों पर भी निगरानी बढ़ाई गई थी। पुलिस का तर्क है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है और किसी भी समूह को जबरन बैरिकेड पार कर शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रशासन की चिंता इस बात को लेकर भी रही कि भीड़ के चंडीगढ़ में प्रवेश करने से यातायात, सुरक्षा और स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कार्यक्रम प्रभावित हो सकते थे। इसलिए पहले से ही कई मार्गों पर बैरिकेडिंग और पुलिस तैनाती की गई थी। टकराव के बाद पुलिस ने मामले दर्ज करने और हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की है। कुछ रिपोर्टों में 21 लोगों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख है, जिनमें शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान और उनके बेटे ईमान सिंह मान के नाम भी बताए गए हैं। पुलिस का आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने का प्रयास किया।

■ **सरकारें मानवीय व कानूनी दृष्टिकोण अपनाएं: मोर्चा...**
मोर्चे के नेताओं का कहना है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक दल के हित में नहीं, बल्कि लंबे समय से जेलों में बंद सिख बंदियों के अधिकारों से जुड़ा है। उनका तर्क है कि जिन कैदियों ने अदालतों से मिली सजा पूरी



कर ली है, उनके मामलों में सरकारों को मानवीय और कानूनी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आंदोलनकारी यह भी सवाल उठाते रहे हैं कि पैरोल और रिहाई से जुड़े मामलों में अलग-अलग बंदियों के साथ अलग व्यवहार क्यों किया जाता है। मोर्चे ने इस मुद्दे पर पंजाब के व्यापक पंथक और मानवाधिकार विमर्श से भी जोड़ा है। कई किसान, धार्मिक और सामाजिक संगठन समय-समय पर आंदोलन को समर्थन देते रहे हैं। इस साल जुलाई में भी बंदी सिंहों की रिहाई को लेकर पंजाब में रेल रोकों आंदोलन किया गया था। सरहिंद में हुए प्रदर्शन के कारण दिल्ली-अमृतसर-जम्मू रेल मार्ग पर 13 से अधिक ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई थी। इससे साफ है कि आंदोलन का असर अब केवल मोहाली तक सीमित नहीं है।

■ **सरकार के सामने दोहरी चुनौती...**
मामले में पंजाब सरकार की स्थिति भी आसान नहीं है। एक तरफ प्रदर्शनकारियों की मांगों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक दबाव है, दूसरी तरफ कानून-व्यवस्था बनाए रखना उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। बंदियों की रिहाई के हर मामले में

संबंधित जेल, अदालत, राज्य और केंद्र के अधिकार क्षेत्र अलग-अलग हो सकते हैं। इसलिए राज्य सरकार के लिए सभी मामलों में सीधे निर्णय लेना संभव नहीं होता। यही वजह है कि बंदी सिंहों का मुद्दा कई वर्षों से केंद्र और पंजाब सरकार के बीच जिम्मेदारी के सवाल से भी जुड़ता रहा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी समेत कई सिख संगठनों ने भी इस विषय को उठाया है। हाल में एसजीपीसी ने राष्ट्रपति के नाम पंजाब के राज्यपाल को एक ज्ञापन देकर नौ सिख बंदियों की रिहाई की मांग रखी थी। इसमें ऐसे बंदियों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनके बारे में समिति का दावा है कि उन्होंने उम्रकैद से अधिक अवधि जेल में बिताई है।

■ **यातायात पर तत्काल असर...**
चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर लंबे समय से चल रहे आंदोलन का सबसे सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। वाईपीएस चौक, सेक्टर 52-53, मटौर बैरियर और आसपास के मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था के कारण वाहनों को वैकल्पिक रास्तों से भेजना पड़ता है। प्रदर्शन के बड़े कार्यक्रमों के दौरान मोहाली से चंडीगढ़ आने वाले प्रमुख

रास्तों पर अतिरिक्त दबाव बनता है और अंदरूनी सड़कों पर भी जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। पहले भी मोर्चे के मार्च के दौरान चंडीगढ़ के प्रवेश और निकास मार्गों पर बैरिकेडिंग के कारण मोहाली की आंतरिक सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ा था। ऐसे हालात में कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों, विद्यार्थियों, मरीजों और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को सबसे अधिक परेशानी होती है। ट्राईसिटी की भौगोलिक स्थिति इस समस्या को और गंभीर बनाती है। चंडीगढ़ और मोहाली के बीच बड़ी संख्या में लोग रोजाना नौकरी, कारोबार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवाजाही करते हैं। इसलिए सीमा पर कुछ घंटे की भी यातायात बाधा का असर कई किलोमीटर तक दिखाई दे सकता है।

■ **पहले भी बन चुका है हिंसा का केंद्र:**
यह पहली बार नहीं है जब कौमी इंसाफ मोर्चा और पुलिस आमने-सामने आए हों। फरवरी 2023 में भी सेक्टर 52-53 की सीमा पर हिंसक टकराव हुआ था। उस समय पुलिस के अनुसार कई पुलिसकर्मी घायल हुए और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचा था। मामले में प्राथमिकी दर्ज

कर कई लोगों को नामजद किया गया था। बाद में कुछ आरोपियों की पहचान बताने वालों के लिए इनाम की घोषणा भी की गई थी। जनवरी 2025 में भी मोर्चे के दूसरे वर्ष पूरे होने के मौके पर चंडीगढ़ की ओर मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था तथा कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी। उस समय भी चंडीगढ़ के कई प्रवेश मार्गों पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी और यातायात प्रभावित हुआ था। इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि मौजूदा विवाद अचानक पैदा हुआ मामला नहीं है। लंबे समय से चल रहा धरना, बार-बार चंडीगढ़ कूच की कोशिश और पुलिस की बैरिकेडिंग ने दोनों पक्षों के बीच अविश्वास को बढ़ाया है। इसलिए हर प्रदर्शन से पहले पुलिस बल बढ़ाना स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता।

■ **21 अगस्त का बंद अगली परीक्षा...**
स्वतंत्रता दिवस की घटना के बाद कौमी इंसाफ मोर्चा ने 21 अगस्त को पंजाब बंद का आह्वान किया है। इससे प्रशासन के सामने अगली बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। यदि बंद व्यापक

रूप लेता है तो बाजार, सार्वजनिक परिवहन, औद्योगिक गतिविधियों और सड़कों पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि बंद की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने सामाजिक, धार्मिक, किसान और राजनीतिक संगठन इसका समर्थन करते हैं। प्रशासन के लिए चुनौती यह होगी कि बंद और प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था भी बनी रहे और आम नागरिकों के मौलिक आवागमन पर अनावश्यक असर न पड़े। वहीं मोर्चे के लिए भी यह सवाल महत्वपूर्ण होगा कि आंदोलन को प्रभावी बनाए रखते हुए उसे हिंसक टकराव से कैसे दूर रखा जाए।

■ **समाधान बातचीत से ही संभव...**
मौजूदा हालात यह संकेत देते हैं कि चंडीगढ़-मोहाली सीमा पर केवल बैरिकेड बढ़ाने या पुलिस बल तैनात करने से समस्या खत्म नहीं होगी। बंदी सिंहों के मामलों में कानूनी स्थिति अलग-अलग है और प्रत्येक मामले की स्थिति स्पष्ट करके संबंधित सरकारों तथा संस्थाओं को संवाद का रास्ता तलाशना होगा। आंदोलनकारी पक्ष को भी अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से रखने और सार्वजनिक संपत्ति तथा पुलिसकर्मियों को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। सबसे जरूरी है कि दोनों पक्षों के बीच नियमित संवाद का कोई प्रभावी माध्यम बने। यदि बातचीत के जरिए लंबित मामलों की कानूनी स्थिति, पैरोल, रिहाई और अधिकार क्षेत्र जैसे मुद्दों पर स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाता है तो लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम किया जा सकता है। फिलहाल 21 अगस्त का प्रस्तावित बंद और उसके पहले की सुरक्षा तैयारियां यह तथ्य करेगी कि यह विवाद बातचीत की दिशा में बढ़ता है या चंडीगढ़-मोहाली सीमा एक बार फिर टकराव का केंद्र बनती है।

6.45 करोड़ से एस्केलेटर, जल एटीएम जैसी कई सुविधाएं विकसित होंगी
मनसा देवी मंदिर को जाने वाले श्रद्धालुओं की राह होगी आसान

समर न्यूज़ | पंचकूला

हरियाणा के पंचकूला स्थित प्रसिद्ध माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की आवाजाही और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए करीब 6.45 करोड़ रुपये की पुनर्विकास योजना तैयार की गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की इस परियोजना में एस्केलेटर, नया प्रवेश कक्ष और मुख्य द्वार, बेहतर पहुंच मार्ग तथा श्रद्धालुओं के लिए कई नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

परियोजना का उद्देश्य मंदिर परिसर में भीड़ के दबाव के बीच आवागमन को सुगम बनाना और खासकर बुजुर्गों व दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की राह आसान करना है। योजना के तहत निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं और 26 अगस्त तक बोलीयां जमा की जा सकती हैं। काम शुरू होने के बाद इसे नौ महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना की सबसे अहम सुविधाओं में पार्किंग क्षेत्र से मंदिर के दरबार तक एस्केलेटर लगाना शामिल है।

इसे मौजूदा सीढ़ियों के साथ बनाया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं के पास आने-जाने के लिए अतिरिक्त विकल्प हो। मंदिर तक पहुंचने में बड़ी संख्या में सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऐसे में एस्केलेटर से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और बच्चों के साथ आने वाले परिवारों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है। एचएसवीपी के अधिकारियों के अनुसार एस्केलेटर मौजूदा सीढ़ी मार्ग के समानांतर रहेगा। पुनर्विकास योजना में मंदिर के लिए नया प्रवेश कक्ष और मुख्य द्वार तैयार करने का भी प्रस्ताव है। इसके



साथ शक्ति चौक और मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क के आसपास भी सुधार कार्य किए जाएंगे। योजना का मकसद केवल नए ढांचे खड़े करना नहीं, बल्कि मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही को अधिक व्यवस्थित करना है। इससे बड़े धार्मिक आयोजनों और नवरात्र जैसे अवसरों पर भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

■ **जल एटीएम और अन्य सुविधाएं...**
श्रद्धालुओं के लिए प्रस्तावित सुविधाओं में जल एटीएम, नई सीढ़ियां, मंदिर तक जाने वाला गलियारा, उपासना स्थल और गुंबद संरचना भी शामिल हैं। इन सुविधाओं के साथ परिसर के सौंदर्यीकरण और सुरक्षात्मक कार्य भी किए जाएंगे। शक्ति चौक के शेष हिस्से में सजावटी रोशनी और लैंडस्केपिंग का काम किया जाना है।

■ **मंदिर परिसर में इससे पहले भी कई विकास योजनाओं पर काम हुआ है।**
मंदिर परिसर में संस्कृत महाविद्यालय के नए भवन का निर्माण जारी है। नया गलियारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा प्रस्तावित है।

■ **नालों के सुधार की बड़ी योजना...**
मंदिर के आसपास बुनियादी सुविधाओं को लेकर केवल परिसर तक सीमित काम नहीं हो रहा है। पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण ने शहर से गुजरने वाले दो बरसाती नालों के सुधार और सौंदर्यीकरण के लिए 95.42 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की है। इनमें मनसा देवी मंदिर से राजीव-इंद्र कॉलोनी होते हुए पंजाब सीमा तक जाने वाला करीब 5.60 किलोमीटर लंबा जलधारा मार्ग भी शामिल है। योजना में नालों के किनारे पैदल और साइकिल ट्रैक, रोशनी, पौधरोपण, पुल और कचरा रोकने के लिए सुरक्षा जाल जैसी सुविधाएं प्रस्तावित हैं।

■ **श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ चुनौती भी:**
यहां वर्षभर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और नवरात्र जैसे पर्वों पर भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। नई सुविधाओं की सफलता केवल निर्माण पूरा होने से तय नहीं होगी, बल्कि उनके नियमित रखरखाव, साफ-सफाई, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन पर भी निर्भर करेगी। परिसर गर्मियों में सुबह चार बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, जबकि आरती भी सुबह और शाम निर्धारित समय पर होती है।

समर न्यूज़। चंडीगढ़

शहर में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को सख्त करने की तैयारी है। चंडीगढ़ नगर निगम के नए ठोस कचरा प्रबंधन उपनियम-2026 के मसौदे में घरों, दुकानों, संस्थानों और बड़े कचरा उत्पादकों के लिए कचरे का स्रोत पर ही अलग-अलग करना अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौजूदा व्यवस्था की तुलना में अधिक जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम ने मसौदे को मंजूरी देने के बाद अब आम लोगों और संबंधित पक्षों से 15 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इसके बाद अंतिम मसौदा तैयार कर अधिसूचना जारी की जाएगी। नए नियमों के तहत घरों और अन्य कचरा उत्पादकों को कचरे को चार श्रेणियों में अलग करना होगा। गीला या जैविक कचरा, सूखा और पुनर्चक्रण योग्य कचरा, घरेलू खतरनाक कचरा तथा सैनिटरी कचरे को अलग-अलग रखना होगा। इसके लिए रंग आधारित चार डिब्बों की व्यवस्था प्रस्तावित है। कचरा संग्रहण और परिवहन के दौरान भी अलग किए गए कचरे को दोबारा मिलाते पर रोक रहेगी। बड़े कचरा उत्पादकों को बागवानी और निर्माण संबंधी कचरे को भी अलग रखना होगा। मसौदे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उल्लंघन पर प्रस्तावित कड़े आर्थिक दंड हैं। थोक कचरा उत्पादकों और निवासी कल्याण संघों के लिए गंभीर उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना 1.5 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। वहीं घर, दुकान या अन्य प्रतिष्ठान द्वारा कचरे को निर्धारित तरीके से अलग नहीं करने पर उल्लंघन की



प्रकृति के अनुसार दंड का प्रावधान है। कचरे को चार श्रेणियों में अलग कर नहीं सौंपने पर आवासीय क्षेत्रों में 400 रुपये का जुर्माना प्रस्तावित है। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने पर 500 रुपये, पान या गुटखा थूकने पर 500 रुपये और सार्वजनिक स्थान पर खुले में शौच या पेशाब करने पर 200 रुपये के दंड का प्रावधान है। जल स्रोतों में कचरा डालने पर 25 हजार रुपये तथा अवैध रूप से कचरा फेंकने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। स्ट्रीट वेंडर द्वारा कचरे का उचित प्रबंधन नहीं करने पर 1,000 रुपये का दंड प्रस्तावित है। होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल जैसे बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर उल्लंघन की स्थिति में एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

■ **उपयोग शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज:**
नए उपनियमों पर चर्चा के दौरान नगर निगम सदन ने कचरा संग्रहण के उपयोग शुल्क में प्रस्तावित बढ़ोतरी को मंजूरी नहीं दी। मसौदे में छोटे मकानों से लेकर बड़े मकानों तक शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव था। दो मरले तक के मकानों के लिए 100 रुपये, दो से 10 मरले

तक 200 रुपये, 10 मरले से एक कनाल तक 400 रुपये, एक से दो कनाल तक 500 रुपये और दो कनाल से अधिक के मकानों के लिए 700 रुपये मासिक शुल्क प्रस्तावित किया गया था। स्ट्रीट वेंडरों के लिए भी शुल्क 50 से बढ़ाकर 100 रुपये करने का प्रस्ताव था, लेकिन सदन ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिलहाल आम घरों पर प्रस्तावित अतिरिक्त मासिक बोझ लागू नहीं होगा।

■ **स्ट्रीट वेंडरों और कारोबारियों की भी जिम्मेदारी:**
नए नियम केवल घरों तक सीमित नहीं होंगे। स्ट्रीट वेंडरों को अपने कारोबार से निकलने वाला भोजन का कचरा, डिस्पोजेबल प्लेट, कप, डिब्बे, रैपर, फल-सब्जियों का कचरा आदि रखने के लिए अलग पात्र रखने होंगे और उसे नगर निगम द्वारा तय स्थान या वाहन को सौंपना होगा। हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर और इसी तरह के प्रतिष्ठानों के लिए भी अलग व्यवस्था प्रस्तावित है। मानव बाल और अन्य जैविक कचरे को अलग ढंग से रखने व इस्तेमाल किए ब्लेड और दूसरे खतरनाक कचरे को अलग संग्रहित कर संग्रहकर्ता को सौंपना होगा।

■ **थोक कचरा उत्पादकों पर ज्यादा जिम्मेदारी:**
नियमों में बड़े कचरा उत्पादकों के दायरे को भी व्यापक बनाया गया है। इसमें बड़े आवासीय परिसर, संस्थान, होटल, अस्पताल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और अन्य ऐसे परिसर शामिल हो सकते हैं जहां कचरे की मात्रा काफी अधिक है। इन्हें पंजीकरण कराने, स्रोत पर कचरा अलग करने, जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रसंस्करण की व्यवस्था करने और संबंधित रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी दी जाएगी। पहले प्रस्ताव में 20 हजार वर्ग मीटर या अधिक क्षेत्रफल, प्रतिदिन 40 हजार लीटर पानी की खपत या प्रतिदिन 100 किग्रा कचरा पैदा करने जैसी कसौटियों को थोक कचरा उत्पादक की पहचान के लिए इस्तेमाल किया गया था।

■ **हर साल बढ़ सकते हैं दंड:**
मसौदे में जुर्माने और प्रशासनिक शुल्क को भी हर साल पांच प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह उपयोग शुल्क में भी सालाना पांच प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान मसौदे में शामिल था। हालांकि मौजूदा क्रिया में उपयोग शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव को सदन ने खारिज कर दिया है। अग्रिम भुगतान करने वाले

उपभोक्ताओं को कुछ राहत देने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। नगर निगम का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि कचरे की मात्रा घटाना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और कचरा निस्तारण केंद्रों पर पड़ने वाला दबाव कम करना है। केंद्रीय स्तर पर भी ठोस कचरा प्रबंधन के नए नियम 2026 लागू किए जा चुके हैं, जिसके अनुरूप स्थानीय निकायों को अपनी व्यवस्था तैयार करनी है। चंडीगढ़ नगर निगम ने अपनी वेबसाइट पर ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2026 का दस्तावेज भी उपलब्ध कराया है।

■ **अब जनता की बारी:**
नगर निगम ने मंजूर मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। 15 दिन की अवधि में निवासी, बाजार संगठन, आरडब्ल्यूए, स्ट्रीट वेंडर, संस्थान और अन्य संबंधित पक्ष अपनी आपत्तियां या सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद प्राप्त सुझावों की समीक्षा कर अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नियमों का बड़ा हिस्सा सीधे आम नागरिकों की रोजमर्रा की आदतों से जुड़ा है।

■ **नियम के साथ व्यवस्था भी जरूरी:**
नए उपनियमों में जिम्मेदारी नागरिकों और कारोबारियों पर बढ़ाई गई है, लेकिन सफल क्रियान्वयन के लिए नगर निगम की भूमिका भी उतनी ही अहम होगी। अलग-अलग श्रेणी का कचरा लेने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, नियमित संग्रहण, कर्मचारियों की निगरानी और शिकायतों के त्वरित निपटारे के बिना केवल जुर्माना लगाने से अपेक्षित परिणाम हासिल करना मुश्किल होगा। अब निगाहें 15 दिन की सुझाव अवधि पर हैं।

हिमाचल में प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में होगी बड़ी कटौती, एचआरटीसी बेड़े में शामिल होंगी 1,000 और बसें

जल्द ही जल्द ही 200 हाइड्रोजन बसें भी शामिल करने की तैयारी, सीएम सुक्खू बोले- हिमाचल में अफसरों की फौज नहीं, योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले अधिकारी चाहिए

संज़ु | शिमला
समर न्यूज़

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द सिंह सुक्खू ने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए सरकार ने एचआरटीसी के बेड़े में 1,000 नई बसें खरीदने की फाइल को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 300 इलेक्ट्रिक बसें दी जा चुकी हैं और जल्द ही 200 हाइड्रोजन बसें भी बेड़े में शामिल होंगी, जो एक बार चार्ज होने पर 300 से 380 किलोमीटर तक का सफर तय करेंगी।

नई बसों के 12 साल के मटेनेंस का टेंडर जारी कर भुगतान कर दिया गया है। यदि बस खराब होती है, तो कंपनियों पर पेनल्टी लगाने का सख्त प्रावधान रखा गया है। सुक्खू सरकार का दावा है कि बेहतर माइलेज और

चंडीगढ़ जैसे घाटे वाले रूटों पर सुचारू संचालन से एचआरटीसी अगले 5 वर्षों में पूरी तरह मुनाफे की स्थिति में आ जाएगी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कहा कि हिमाचल प्रदेश को बड़ी संख्या में उच्च अधिकारियों की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है जो सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।

सरकार प्रशासनिक ढांचे को अधिक प्रभावी और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के उद्देश्य से अधिकारियों के स्वीकृत पदों में कटौती करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के स्वीकृत पदों की संख्या 153 से



घटाकर 130 की जाएगी। इसी तरह भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के 118 पदों को घटाकर 83 किया जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 96 स्वीकृत पदों में भी कमी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्रशासनिक काम 100 से 110 आईएएस अधिकारियों के साथ भी चल सकता है, लेकिन अधिकारियों से मिले सुझावों के बाद

फिलहाल 130 पद रखने का निर्णय लिया गया है।

सुक्खू ने कहा कि अधिकारियों की संख्या कम करने से सरकार को करीब 200 करोड़ रुपये की बचत होगी। ऐसे में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग जनहित और विकास कार्यों में करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं, सरकार उन्हें

युवाओं और आम जनता के लिए रोजगार व राहत

योजनाओं की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ई-बस खरीदने वाले युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ 5 साल तक 80,000 प्रति माह और डीजल बसें पर 30% सब्सिडी के साथ 50,000 प्रति माह देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा छात्रों को 5 प्रतिदिन में कॉलेज पास और महिलाओं को किराए में 50% की छूट जारी रहेगी।नेता प्रतिपक्ष के बयान पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के एरियर और राज्य की वित्तीय स्थिति पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध का सम्मान है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का पे-एरियर जारी कर दिया गया है, जबकि तृतीय श्रेणी के लिए 35% और प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए 15% एरियर देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने पूर्व सरकार पर 10,000 करोड़ रुपये की देनदारी छोड़ने और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) बंद होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद किसी की पेंशन या वेटन रोके बिना राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के 18 अगस्त को प्रस्तावित मंडी दौरे को लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह दौरा राजनीतिक जनसभा के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि आपका के दौरान प्रियंका गांधी मंडी पहुंची थीं और उन्होंने एक स्कूल के निर्माण का वादा किया था। इसी वादे को पूरा करने के सिलसिले में वह मंडी आ रही हैं और स्कूल के बच्चों से मुलाकात करेंगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, सितंबर में सोलन में प्रस्तावित राजनीतिक जनसभा में भी प्रियंका गांधी के शामिल होने का कार्यक्रम है।विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को लेकर गंभीर है और उन्हें चरणबद्ध तरीके से विभिन्न लाभ दिए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी पिछली सरकार के कार्यकाल पर भी नजर डालनी चाहिए, जब प्रदेश पर भारी देनदारियां छोड़ी गई थीं।सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक खर्च घटाने के साथ विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाना है।

रोक नहीं रही है और उनकी फाइलों को भी जल्द मंजूरी दी जा रही है।

उन्होंने संकेत दिया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी)

में भी अधिकारियों की संख्या को तर्कसंगत बनाया जाएगा।

नौकरियां नहीं, टैक्स और कर्ज बढ़ा रही सुक्खू सरकार: डॉ. राजीव बिंदल



समर न्यूज़ | शिमला

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीपकमल, शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर बेरोजगारी, बढ़ते टैक्स, महंगाई, कर्ज और विकास कार्यों में कथित उधरवाव को लेकर तीखा हमला बोला।

उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं को एक लाख सरकारी नौकरियां और पांच लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन वादों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में एक लाख सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया था। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार का कार्यकाल लगभग चार वर्ष पूरा होने को है, लेकिन प्रदेश के अनेक विभागों में पद रिक्त हैं और बेरोजगार युवा वर्षों से भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिससे रिक्त पदों की संख्या और बढ़ी है। बेरोजगार युवा लाइब्रेरियों में वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई भर्तियों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

‘पेपर हुआ ही नहीं तो लीक कहां से होगा: कांग्रेस सरकार द्वारा पेपर लीक न होने को उपलब्धि बताए जा रहे हैं। डॉ. बिंदल ने कटाक्ष करते हुए कहा, “पेपर हुआ ही नहीं तो लीक कहां से होगा?” उन्होंने कहा कि सरकार को पारदर्शी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के हुई नियुक्तियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के एक मंत्री



भाजपा के कामों का श्रेय लेने में जुटी सुक्खू सरकार: राजिंद्र गर्ग

सुभाष | बिलासपुर : पूर्व मंत्री राजिंद्र गर्ग ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत विकास कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। बिलासपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए गर्ग ने कहा कि मुख्यमंत्री के हालिया बिलासपुर दौरे के दौरान जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, उनमें से कई कार्य भाजपा सरकार के समय स्वीकृत या शुरू हुए थे।गर्ग ने आरोप लगाया कि सरकार को अपनी विदाई का अहसास हो गया है, इसलिए आनन-फानन में आधे-अधरे कार्यों के उद्घाटन किए जा रहे हैं और नई शिलान्यास पट्टिकाएं लगाकर राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि भराड़ी को तहसील का दर्जा पूर्व भाजपा सरकार ने दिया था। इसी तरह भाजपा शासन में स्वीकृत कई स्वास्थ्य संस्थानों और सरकारी कार्यालयों को वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही डीनोटेफाई कर दिया था, जिन्हें अब दोबारा शुरू करने की घोषणाएं की जा रही हैं। पूर्व मंत्री ने कुमारवी के आईपीडी भवन के उद्घाटन को लेकर भी सवाल उठाए।

स्वयं सैकड़ों लोगों को नियुक्त करने की बात सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि ऐसी नियुक्तियों की प्रक्रिया और संख्या की जांच होनी चाहिए।

■ जनता की जेब पर बढ़ता बोझ: डॉ. बिंदल ने कहा कि सरकार ने आम आदमी की आय बढ़ाने के बजाय उसके खर्च में लगातार वृद्धि की है। पेट्रोल-डीजल पर बढ़े करों और हाल में लगाए गए 60 पैसे प्रति लीटर के अतिरिक्त सेस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सीधे तौर पर आम उपभोक्ता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सरकार के लगभग चौरा चार वर्ष के कार्यकाल में पेट्रोल-डीजल पर बढ़े करों और कीमतों के कारण प्रदेश की जनता पर करीब 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पाद महंगे होने का असर परिवहन लागत के साथ-साथ रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ता है।

■ सीमेंट, राशन व स्टॉप ड्यूटी पर भी निशाना: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की नीतियों से सीमेंट, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का खर्च बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि सीमेंट पर बढ़े टैक्स का असर हिमाचल के उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जबकि प्रदेश स्वयं सीमेंट उत्पादक राज्य है। उन्होंने स्टॉप ड्यूटी में बढ़ोतरी और विभिन्न दस्तावेजों से जुड़े खर्च का भी मुद्दा उठाया। राशन की कीमतों में वृद्धि का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि दाल, तेल, चावल

और आटे के बढ़े दामों से गरीब परिवारों का बजट प्रभावित हुआ है।

■ बस, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल : डॉ. बिंदल ने कहा कि एचआरटीसी से यात्रा करने वाले विद्यार्थी, कर्मचारी, मजदूर और आम नागरिक भी बढ़ते खर्च से प्रभावित हैं। उन्होंने किरायों और रियायतों में बदलाव तथा कुछ रूट बंद होने का मुद्दा उठाते हुए सरकार की परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने बिजली और पानी से जुड़े खर्च में बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए कहा कि आम परिवार का मासिक बजट लगातार दबाव में है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में जांच, दवाइयों और उपचार की उपलब्धता को लेकर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

■ किसान-बागवान भी बढ़ती लागत से परेशान : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि खाद, बीज, कीटनाशक, परिवहन और अन्य कृषि-बागवानी इनपुट महंगे होने से किसानों और बागवानों की उत्पादन लागत बढ़ रही है। जब जनता पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है तो उससे प्राप्त धन का उपयोग कहां किया जा रहा है। डॉ. बिंदल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लिया, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में विकास कार्य अपेक्षित गति से नहीं हो रहे हैं। उन्होंने सड़कों की खराब स्थिति पर भी सवाल उठाए।



अरविंद | हमीरपुर
समर न्यूज़

हमीरपुर में भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कॉल के तहत आयोजित किया गया।

इस दौरान कर्मचारियों ने केंद्र सरकार से बैंक कर्मचारियों और अन्य श्रमिकों से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान करने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों और बैंक कर्मचारियों ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय श्रम मंत्री और

वित्त मंत्री के नाम 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं, जिन पर केंद्र सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

भारतीय मजदूर संघ जिला हमीरपुर के अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लागू करना और बैंकों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करना शामिल है। इसके अलावा कर्मचारियों के हितों से जुड़ी अन्य मांगों को भी ज्ञापन में प्रमुखता से उठाया गया है।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों की कुछ मांगों को स्वीकार किया जा चुका है,

शिमला में दर्दनाक सड़क हादसे में दो पुलिसकर्मियों की गई जान



संज़ु | शिमला
समर न्यूज़

राजधानी शिमला में टालैंड और खलीनी के बीच बीती देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां कार और टैक्टर के बीच हुई जोरदार टक्कर में हिमाचल प्रदेश पुलिस के दो जवानों की मौत हो गई।

हादसे के बाद पुलिस विभाग और मृतकों के परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई है।जानकारी के अनुसार, दोनों पुलिस जवान अपनी ऑल्टो

कार में सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान टालैंड-खलीनी मार्ग पर सामने से आ रहे एक टैक्टर के साथ उनकी कार की भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों जवान गंभीर रूप से हादसे की चपेट में आ गए।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

खेल

मंडी में पहली ट्रायम्फ एफसी ऑल ओपन फुटसल चैंपियनशिप शुरू

धर्मवीर | मंडी
समर न्यूज़

ट्रायम्फ एफसी हिमाचल की ओर से मंडी में पहली बार आयोजित ऑल ओपन फुटसल चैंपियनशिप का विधिवत शुभारंभ पुलिस अधीक्षक मंडी मनोज कुमार, आईपीएस ने किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए खेलों को युवाओं के सर्वांगीण विकास और नशे से दूर रखने का प्रभावी माध्यम बताया।

ट्रायम्फ एफसी हिमाचल के प्रधान सुशांत शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल दस टीमों हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्राईअम्फ यूथ क्लब का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखना है।



उन्होंने कहा कि फुटसल जैसे खेल युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और सकारात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चैंपियनशिप में ट्रायम्फ एफसी मंडी, ट्रायम्फ यूथ क्लब मंडी, सुंदरनगर एफसी ए, सुंदरनगर एफसी बी, एसटीसी एफसी ए, एसटीसी एफसी बी, केंद्रीय विद्यालय मंडी एफसी, तकसिला एफसी, ऑल

स्टारज एफसी और बल्ह एफसी की टीमों भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में ट्रायम्फ यूथ क्लब मंडी और केंद्रीय विद्यालय मंडी एफसी आमने-सामने रहे। दोनों टीमों के बीच जोरदार संघर्ष देखने को मिला और रोमांचक मुकाबले में ट्रायम्फ यूथ क्लब मंडी ने अंतिम क्षणों में 11-9 से जीत दर्ज की।दूसरे मैच में एसटीसी एफसी ए

और सुंदरनगर एफसी बी के बीच मुकाबला हुआ। सुंदरनगर एफसी बी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18-5 से मुकाबला अपने नाम किया। तीसरे मैच में ऑल स्टारज एफसी और तकसिला एफसी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। निर्धारित समय तक दोनों टीमों 2-2 की बराबरी पर रहीं। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में ऑल स्टारज एफसी ने 5-4 से

बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर ग्रामीणों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

अरविंद | हमीरपुर
समर न्यूज़

राष्ट्रीय राजमार्ग-103 पर डुगधा के समीप लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर लाहड़ क्षेत्र के ग्रामीणों में रोष है। समस्या के समाधान की मांग को लेकर कांग्रेस नेता डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा की अगुवाई में ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात की ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर डिवाइडर लगाने, लिंक रोड के संगम स्थल पर कन्वेक्स लेंस लगाने तथा वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग उठाई।

ग्रामीणों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग-103 पर कोहली से चील बहल तक निर्माण कार्य जारी है। हथलीखड्ड पर पुल का निर्माण पूरा न होने के कारण कोहली की ओर से आने वाले वाहनों को डुगधा डायवर्शन से होकर गुजरना पड़ रहा है।

हमीरपुर में बैंक कर्मियों का प्रदर्शन, ओपीएस व पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग

श्रमिकों की मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

भूपेंद्र | सोलन
समर न्यूज़

भारतीय मजदूर संघ हिमाचल प्रदेश ने देशभर के श्रमिकों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपायुक्त सोलन के माध्यम से ज्ञापन भेजा।

संघ के उप महामंत्री देवी दत्त तनवर ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, ठेका-आउटसोर्सिंग व्यवस्था और श्रम विरोधी नीतियों के कारण करोड़ों श्रमिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रांची में 26 से 28 जुलाई 2026 तक आयोजित अखिल भारतीय कार्यसमिति की बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर यह मांग पत्र सौंपा गया। ज्ञापन में भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के



लिए न्यूनतम मासिक वेतन 30 हजार रुपये निर्धारित करने की मांग प्रमुखता से उठाई है। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेतन सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करने की मांग की गई है। संघ ने ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह करने के साथ पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की भी मांग रखी।इसके अलावा ईपीएफ की वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने तथा बोनस गणना की सीमा 7 हजार से बढ़ाकर

18 हजार रुपये किए जाने की मांग की गई है। बोनस पात्रता की सीमा भी 21 हजार से बढ़ाकर 42 हजार रुपये करने की मांग ज्ञापन में शामिल है।संघ ने आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिड-डे-मील, एनएचएम समेत विभिन्न योजनाओं में कार्यरत स्कीम वर्करों को नियमित कर पक्का कर्मचारी बनाने की मांग की।

उन्हें वेतन संहिता-2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 के दायरे में शामिल करने पर जोर दिया गया।ठेका और संविदा कर्मचारियों के लिए ‘समान काम, समान वेतन’ लागू करने की मांग भी उठाई गई। देवी दत्त तनवर ने केंद्र सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार कर श्रमिकों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया।

लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेकर

कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों और मजदूरों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर

संगठन आगे भी संघर्ष जारी रखेगा। संगठन ने केंद्र सरकार से मांगों पर सकारात्मक और शीघ्र कार्रवाई की उम्मीद जताई।

चिंतपूर्णी मेले में आवारा पशुओं से बढ़ा खतरा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवाल

विकास | चिंतपूर्णी
समर न्यूज़

प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में चल रहे मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की डबल लाइनें लग रही हैं, वहीं मुख्य बाजार और संपर्क मार्गों पर खुलेआम घूम रहे बेसहारा पशु सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं।

भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में बैलों के घूमने से किसी भी समय अफरा-तफरी या भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है।मेले के चलते चिंतपूर्णी बाजार में दिनभर श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है। ऐसे में अचानक पशुओं की भीड़ में घुसने से लोग घबराकर भाग सकते हैं। इससे विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने प्रशासन से बाजार



व मंदिर क्षेत्र के आसपास घूम रहे बेसहारा पशुओं को तत्काल हटाने की मांग की है।

पशुपालन विभाग ऊना के उपनिदेशक डॉ. वीरेंद्र पटियाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को रेस्क्यू करने और हटाने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्थानीय निकायों, पंचायतों, नगर कमेटियों तथा संबंधित हाईवे अथॉरिटी की है। पशुपालन विभाग की भूमिका मुख्य रूप से पशुओं को

प्राथमिक उपचार और आवश्यक ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाने तक सीमित है। उन्होंने कहा कि विभाग के पास सड़कों से पशुओं को पकड़ने के लिए पर्याप्त मैनपावर उपलब्ध नहीं है। स्थानीय पंचायत या निकाय यदि पशुओं को काबू करने और पकड़ने की व्यवस्था करें, तो विभाग के पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचकर उन्हें बेहोश करने का इंजेक्शन दे सकते हैं। बिना स्थानीय स्तर पर सहयोग के पशुओं को सुरक्षित तरीके से पकड़ना मुश्किल है।

सबसे बड़ा सवाल- बलौंगी पर आखिर किसका अधिकार? जिम्मेदारी पर छिड़ा ‘कन्प्यूजन का खेल’

बलौंगी में निर्माण को लेकर टाउन प्लानर और एसीए गमाडा के दावों में विरोधाभास

●एसीए गमाडा का दावा: क्षेत्र नगर निगम के अधीन ●एमटीपी ने कहा: अभी एमसी के दायरे में नहीं आया

सागर पाहवा | मोहाली
समर न्यूज़

बलौंगी में तेजी से बढ़ते निर्माण कार्य और कथित अवैध पीजी निर्माण अब सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि विभागीय दावों में भी उलझते नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि जिम्मेदारी तय करने को लेकर ही दो अहम विभाग आमने-सामने आ गए हैं, जिससे पूरे मामले में असमंजस और गहरा गया है।

बलौंगी में लगातार नए पीजी और बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो रही हैं। कई जगहों पर निर्माण नियमों की अनदेखी के आरोप भी खुलेआम लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा इस बात को लेकर है कि आखिर बलौंगी पर किसका अधिकार है।

एसीए गमाडा के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि बलौंगी क्षेत्र अब नगर निगम के अधीन आ चुका है, इसलिए निर्माण की निगरानी, नक्शों की मंजूरी और अवैध निर्माण पर



दुविधा के कारण लोग हो रहे परेशान

स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय इस “कन्प्यूजन” का सीधा फायदा निर्माणकर्ता उठा रहे हैं। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि कई जगह बिना स्पष्ट अनुमति के पीजी और अन्य इमारतों का निर्माण धड़ल्ले से जारी है। लोगों का सवाल है कि जब जिम्मेदारी ही तय नहीं है, तो कार्रवाई कौन करेगा? यदि क्षेत्र वास्तव में नगर निगम के अधीन आ चुका है, तो निगम को तुरंत सक्रिय होकर ऐसे निर्माणों की जांच करनी चाहिए। वहीं अगर क्षेत्र अभी भी गमाडा के अधीन है, तो संबंधित प्राधिकरण को स्थिति स्पष्ट कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।

कार्रवाई की जिम्मेदारी पूरी तरह नगर निगम की है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब इस

मुद्दे पर एमटीपी आर्किटेक्ट संदीप सैनी से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने बिल्कुल अलग रख अपनाते हुए

निर्माण कार्य लगातार जारी

सबसे बड़ा सवाल यही है कि बलौंगी आखिर किसके अधिकार क्षेत्र में है? दो जिम्मेदार अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों ने आम लोगों की उलझन और बढ़ा दी है। ऐसे में प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द स्थिति स्पष्ट कर यह बताए कि बलौंगी में निर्माण की अनुमति, निगरानी और अवैध निर्माण पर कार्रवाई का असली अधिकार किसके पास है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई का जिम्मा किसके पास? बलौंगी में निर्माण कार्य लगातार जारी है। यदि यह क्षेत्र नगर निगम के अधीन आ चुका है तो निगम को तुरंत जांच कर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि क्षेत्र अभी निगम के दायरे में नहीं है, तो एसीए गमाडा को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी। नगर निगम सीमा के भीतर आने वाली कॉलोनियों में गवन नवरो संबंधित स्थानीय निकाय के उपनियमों के अनुसार स्वीकृत किए जाते हैं, जबकि नगर निगम सीमा से बाहर की कॉलोनियों के लिए गमाडा के गवन नियम लागू होते हैं।

सरकारी रिकॉर्ड में बलौंगी निगम की सीमा में

सरकारी दस्तावेजों के अनुसार बलौंगी अब मोहाली नगर निगम की सीमा में शामिल है। पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने नवंबर 2025 में मोहाली नगर निगम की सीमा विस्तार की अंतिम अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत बलौंगी समेत कई गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल किया गया। इससे पहले जारी नसीदा अधिसूचना में बलौंगी को बाहर रखा गया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई थीं। बाद में अंतिम अधिसूचना में स्थिति बदल गई और बलौंगी को निगम सीमा में शामिल कर दिया गया।

कहा कि बलौंगी अभी नगर निगम के अधीन नहीं आया है। यानी एक ही क्षेत्र को लेकर दो विभागों के दो

अलग-अलग दावे सामने आ गए हैं, जिससे स्थिति और भी उलझ गई है।

वार्ड-17 में सेंसरी पार्क से बाजारों के विकास तक किए कई काम : दमनप्रीत सिंह बादल

कांग्रेस पार्षद ने किसान आंदोलन से राजनीति में सक्रिय होने तक का सफर किया साझा, बोले - स्थानीय चुनाव में काम और जनता से जुड़ाव सबसे अहम



■ सेक्टर-22 में दिव्यांग बच्चों के लिए सेंसरी पार्क को बताया कार्यकाल की अहम उपलब्धि
शगुन कश्यप। चंडीगढ़
समर न्यूज़

‘मेरा वार्ड, मेरा परिवार’ कार्यक्रम में वार्ड नंबर-17 से कांग्रेस पार्षद दमनप्रीत सिंह बादल ने अपने राजनीतिक सफर और क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों को लेकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि राजनीति में आने का फैसला पहले



से तय नहीं था। किसान आंदोलन के दौरान बिना किसी राजनीतिक पहचान के सेवा करते हुए उन्हें लगा कि व्यवस्था में बदलाव के लिए सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनना ही जरूरी है। बादल ने बताया कि शुरुआती दौर में उनका जुड़ाव कांग्रेस नेता प्रदीप छाबड़ा के साथ रहा। बाद में राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आया और उन्होंने

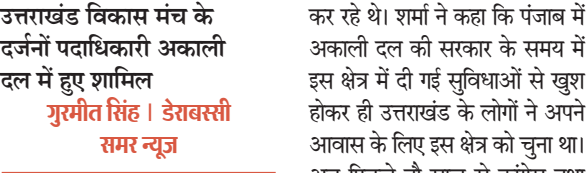
पंचकूला नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ‘एडमिनस्ट्रेटिव आइकॉन’ से सम्मानित

मुकुल शर्मा | पंचकूला
समर न्यूज़

बिफमा म्यूजिक ग्लोबल, वन क्वांटम और माइंड वेदा के संयुक्त तत्वावधान में दैगौर थिएटर में ‘राष्ट्र चेतना के सुर’ संगीतमयी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 30 से अधिक गायकों ने देशभक्ति, सामाजिक चेतना और संगीत का खूबसूरत संगम प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में पंचकूला नगर निगम आयुक्त विनय कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके प्रशासनिक नेतृत्व एवं सामाजिक योगदान के सम्मान में वन क्वांटम



और माइंड वेदा के संस्थापक केवल बिन्दुसार ने उन्हें ‘एडमिनस्ट्रेटिव आइकॉन’ सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान उन्हें बुके, शॉल तथा राष्ट्रभावना के प्रतीक राष्ट्रीय पक्षी मोर का स्मृति-चिह्न भेंट किया गया। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण पंचकूला की उभरती वेस्टर्न सॉन्ग सिंघर एवं कंपोजर हर्षिता बिन्दुसार ‘इनफिनिटी’ की प्रस्तुति रही।



उत्तराखंड विकास मंच के दर्जनों पदाधिकारी अकाली दल में हुए शामिल
गुरमीत सिंह | डेराबस्सी
समर न्यूज़

शिरोमणि अकाली दल के कोषाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक एन.के.शर्मा ने कहा है कि डेराबस्सी विधानसभा हलके की तरक्की में उत्तराखंड के लोगों की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड के लोगों ने यहां आकर अपनी मेहनत के बल पर अलग पहचान बनाई है।

एनके शर्मा उत्तराखंड विकास मंच के पदाधिकारियों तथा उत्तराखंड मूल के लोगों को शिरोमणि अकाली दल में शामिल करने पर उनका स्वागत

कर रहे थे। शर्मा ने कहा कि पंजाब में अकाली दल की सरकार के समय में इस क्षेत्र में दी गई सुविधाओं से खुश होकर ही उत्तराखंड के लोगों ने अपने आवास के लिए इस क्षेत्र को चुना था। अब पिछले नौ साल से कांग्रेस तथा आम आदमी पार्टी की तरफ से यहां रहने वाले बाहरी राज्य के लोगों की समस्याओं के समाधान की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। शर्मा ने कहा कि पंजाब में अगले साल अकाली दल की सरकार के सत्ता में आने के बाद उत्तराखंड के लोगों की प्रत्येक समस्या का पहल के आधार पर समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तराखंड विकास मंच के मनमोहन सिंह, प्यारा सिंह, देवी सिंह, वी.एस. रावत एवं अन्य मौजूद थे।

बलबीर सिंह सिद्धू ने किया बठलाणा का दौरा

कहा- सड़क पर जगह-जगह गड्डे, बारिश का जमा पानी लोगों के लिए गंभीर परेशानी

मुकुल शर्मा | पंचकूला
समर न्यूज़

आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने लांडरा-बनूड रोड से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित गांव बठलाणा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव की खस्ताहाल सड़क दिखाते हुए आम आदमी पार्टी सरकार के विकास के दावों की असलियत लोगों के सामने रखी।

सड़क पर जगह-जगह पड़े गहरे गड्डे और बारिश का जमा हुआ पानी लोगों के लिए गंभीर परेशानी का कारण बने हुए हैं। बलबीर सिंह सिद्धू



ने कहा कि आप सरकार पिछले साढ़े चार वर्षों से विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। गांवों की बुनियादी सुविधाओं की ओर कोई उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा और लोग आज भी टूटी सड़कों, गंदे पानी और खराब बुनियादी ढांचे

से जूझ रहे हैं। बलबीर सिंह सिद्धू ने हलका विधायक कुलवंत सिंह से सीधा सवाल करते हुए कहा कि अगर साढ़े चार वर्षों में आप सरकार ने वास्तव में विकास किया है, तो वह लोगों को अपना कोई एक ऐसा काम गिनाएँ, जो जमीन पर दिखाई देता हो।

पेज 1 एंकर स्टोरी

देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना का हुआ उत्सव

सीजीसी यूनिवर्सिटी, मोहाली में राष्ट्रीय ध्वजारोहण एवं समर्पण समारोह

समर न्यूज़ | पंचकूला

सीजीसी यूनिवर्सिटी, मोहाली में ग्रेट नवभारत मिशन फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय ध्वजारोहण और समर्पण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई जानी-मानी हस्तियां, शिक्षाविद, छात्र और यूनिवर्सिटी परिवार के लोग एक साथ आए और सबने मिलकर देशभक्ति, एकता और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने संकल्प को साझा किया। समारोह की गरिमा तीन प्रतिष्ठित हस्तियों की गरिमामयी उपस्थिति से और बढ़ गई। कुरुक्षेत्र से सांसद



तथा प्लेग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवीन जिंदल ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई। वहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेट्जिक अलायंस के अध्यक्ष डॉ. जगविंदर सिंह विर्क तथा शुभम अग्रवाल, आईपीएस, एसएसपी, फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)

ने विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई। मुख्य अतिथि, कुरुक्षेत्र से सांसद एवं प्लेग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवीन जिंदल ने प्रत्येक भारतीय को

गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिलाने के अपने प्रेरणादायी संघर्ष की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 1992 के भारत लौटने के बाद उन्होंने गर्व के साथ तिरंगा फहराना शुरू किया, लेकिन उस समय उन्हें कई प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। जिंदल ने जेन जी और युवा नेतृत्व से कड़ी मेहनत करने, सहयोग की भावना को अपनाने तथा ‘विकसित भारत’ के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। सीजीसी यूनिवर्सिटी, मोहाली के संस्थापक व चांसलर एस. रशपाल सिंह धालीवाल ने कहा कि देशभक्ति

सिर्फ कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल हमारी आजादी का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के बलिदान, वर्तमान पीढ़ी की आकांक्षाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत भारत के वादे को दर्शाता है। सीजीसी यूनिवर्सिटी, मोहाली के एमडी अर्श धालीवाल ने कहा कि राष्ट्र निर्माण का असली मतलब हमारे युवाओं को बड़े सपने देखने, जिम्मेदारी से काम करने के लिए सक्षम बनाना है।

पुलिस में बड़ा फेरबदल: मोहाली से एसपी

रैंक के एक दर्जन अधिकारियों का तबादला

एसपी ऑपरेशन्स, ट्रैफिक, रूरल, इन्वेस्टिगेशन सहित कई अहम पद बदले

नए अधिकारियों की तैनाती, चुनाव से पहले कवायद के तौर पर देखा जा रहा फेरबदल
सागर पाहवा | मोहाली
समर न्यूज़

पंजाब पुलिस में बड़े स्तर पर किए गए फेरबदल के तहत मोहाली जिले में तैनात करीब एक दर्जन एसपी रैंक के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस बदलाव में जिले के कई अहम पुलिस पद प्रभावित हुए हैं। इनमें एसपी ऑपरेशन्स, एसपी हेडक्वार्टर, एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी ट्रैफिक, एसपी रूरल, एसपी पीबीआई, एसपी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, एसपी साइबर क्राइम और एसपी डेराबस्सी जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।

पुलिस विभाग की ओर से इन तबादलों को प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस महकमे में इस बड़े फेरबदल को आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पुलिसिंग व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद के तौर पर भी देखा जा रहा है।

कई अधिकारियों को मोहाली से बाहर भेजा: फेरबदल के तहत एसपी हरसिमरत सिंह को एसपी हेडक्वार्टर रूयनगर नियुक्त किया गया है। वह हाल ही में डीएसपी

डेराबस्सी और राजपुरा की कमान में भी बदलाव

फेरबदल का असर डेराबस्सी और राजपुरा की पुलिसिंग व्यवस्था पर भी पड़ा है। एसपी डेराबस्सी बिकनजीत सिंह बराड़ का तबादला पटियाला कमिश्नरेट के तहत एसपी राजपुरा के पद पर किया गया है। एसपी पृथ्वी चहल को एसपी एनटीएफ रूपनगर और एसपी करनवीर सिंह को एसपी मलेरकोटला नियुक्त किया गया है। वहीं एसपी साइबर क्राइम-2 का भी तबादला कर उन्हें एसपी बडिडा के पद पर तैनात किया गया है।

मोहाली में नए अधिकारियों को जिम्मेदारी

तबादलों के बाद मोहाली में खाली हुए महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की तैनाती भी की गई है। एसपी आकाशदीप सिंह औलख को एसपी ऑपरेशन्स एवं पीबीआई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसपी नवनीत सिंह को एसपी हेडक्वार्टर नियुक्त किया गया है। एसपी नवनीत कौर गिल को एसपी ट्रैफिक और एसपी रमिंदर सिंह को एसपी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है।

चुनाव से पहले पुलिसिंग व्यवस्था पर नजर

एक साथ बड़ी संख्या में एसपी रैंक के अधिकारियों के तबादले को लेकर पुलिस महकमे में चर्चा तेज है। खासतौर पर मोहाली जैसे महत्वपूर्ण जिले में ऑपरेशन्स, ट्रैफिक, इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम और गांधी पुलिसिंग से जुड़े पदों में बदलाव को अहम माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि तबादले प्रशासनिक जरूरतों और बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। वहीं, विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले को चुनावी तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

रैंक से पदोन्नत होकर एसपी बने थे। एसपी गुरिंदरबीर सिंह को एसपी एनटीएफ एवं इन्वेस्टिगेशन, बरनाला लगाया गया है। मोहाली में एसपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभाल रहे नवनीत सिंह का तबादला एसपी इन्वेस्टिगेशन होशियारपुर के तौर पर किया गया है। वहीं एसपी खड्ड मोहित अग्रवाल को एसपी सिटी पटियाला नियुक्त किया गया है। एसपी रूरल मोहाली मनप्रीत सिंह

को एसपी इन्वेस्टिगेशन, संगरूर भेजा गया है। एसपी पीबीआई दीपक सिंह को एसपी स्पेशल ब्रांच, एजीटीएफ मोहाली की जिम्मेदारी दी गई है। एसपी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मोहाली रमनदीप सिंह को एसपी हेडक्वार्टर, होशियारपुर लगाया गया है। एसपी ऑपरेशन्स मोहाली तलविंदर सिंह गिल को एसपी साइबर क्राइम-1 मोहाली की जिम्मेदारी दी गई है।

दिव्यांग और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए झूले व अन्य सुविधाएं

दमनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि अपने कार्यकाल में वार्ड में कई विकास कार्य करवाए गए। सेक्टर-22 में गुरुद्वारा साहिब के सामने बने सेंसरी पार्क को उन्होंने विशेष उपलब्धि बताया। इस पार्क में दिव्यांग और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए झूले एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करावाई गई हैं। उन्होंने बताया कि सेक्टर-22 की किरण सिनेमा मार्केट में पलोरिंग का काम पूरा हो चुका है, जबकि मेगाइल मार्केट समेत अन्य स्थानों पर विकास कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं। सड़कों, गलियों और पार्कों की मरम्मत व रखरखाव के काम भी समय-समय पर करवाए जा रहे हैं।

कूड़ा प्रबंधन बनी बड़ी चुनौती

पार्षद ने वार्ड में कूड़े की समस्या को बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि सेक्टर-22 में व्यावसायिक गतिविधियां, बड़ी संख्या में पीजी और देर रात तक लोगों की आवाजाही होने के कारण घर-घर कचरा संग्रहण वाहन निकलने के बाद भी कई जगह कूड़ा बाहर फेंका जाता है। पुराने कपड़े, गद्दे और अन्य भारी सामान भी खुले में डाल दिए जाने से सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि नगर निगम आयुक्त की पहल पर सेक्टर-22 में छोटे वाहनों के माध्यम से कचरा संग्रहण का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी है, जिससे समस्या कम होने की उम्मीद है।

‘स्वच्छ वार्ड के लिए लोगों का सहयोग जरूरी’

दमनप्रीत सिंह बादल ने वार्डवासियों, खासकर पीजी संचालकों से अपील की कि वे किरायेदारों और विद्यार्थियों को कचरा संग्रहण व्यवस्था की जानकारी दें। गौले और सूखे कचरे को अलग-अलग रखकर निर्धारित वाहन में ही दिया जाए। नगर निगम और पार्षद अपने स्तर पर व्यवस्था बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वार्ड को साफ-सुथरा रखने के लिए लोगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है।

चुनावी राजनीति में कदम रखा। वह आम आदमी पार्टी से भी जुड़े, लेकिन बाद में वापस कांग्रेस में

आ गए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी के साथ-साथ पार्षद का लोगों के बीच रहना,

फोन उठाना और उनकी समस्याओं पर काम करना सबसे महत्वपूर्ण होता है।

ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ विद्यार्थियों ने ली शपथ

प्रयोग फाउंडेशन व सर्वप्रथम फाउंडेशन ने मॉडर्नवेज स्कूल में किया कार्यक्रम

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

सिटी ब्यूटीफुल में प्रयोग फाउंडेशन व सर्वप्रथम फाउंडेशन की ओर से संयुक्त रूप से ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ध्वनि द पीस के माध्यम से स्थानीय सेक्टर 29 स्थित मॉडर्नवेज सोनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरा सैकड़ों विद्यार्थियों ने ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध जागरूकता अभियान में शामिल होने तथा प्रदूषण फैलाने के संबंध में शपथ ली।

दंत रोग चिकित्सक डॉ. कविता शर्मा के मंच संचालन आयोजित कार्यक्रम के दौरान स्कूल प्रिंसिपल इंजी.गिरिश सचदेवा ने कहा कि



ध्वनि प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय है। दोनों संस्थाएं मिलकर सुरक्षित भविष्य के मહેनजर राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्र हित में कार्य कर रही हैं, जिसमें स्कूल का प्रत्येक अस्थापक और विद्यार्थी इसमें साथ है। डॉ.रोमिका वहेरा ने दैनिक दिनचर्या के दौरान विद्यार्थियों द्वारा हैडफोन लगाने, मोटरसाइकिल के पटाखे बजाने, उंची आवाज में म्यूजिक सुनने की

आदतों को ध्वनि प्रदूषण का बड़ा कारण बताया। विषय विशेषज्ञ संजय ओझा ने प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के माध्यम से लागू किए गए नियमों के बारे में बताया। इस अवसर पर ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित स्कूली विद्यार्थियों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

‘वंदे मातरम’ विवाद पर रेखा शर्मा का कांग्रेस पर हमला, सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप

मुकुल शर्मा | पंचकूला
समर न्यूज़

सांसद रेखा शर्मा ने कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान ‘वंदे मातरम्’ को कथित तौर पर बीच में रोके जाने के मामले पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रगीत को रोककर उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। रेखा शर्मा ने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने पर सरकार द्वारा इसे विशेष सम्मान दिया गया,

लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में हुई घटना ने इस सम्मान को धूमिल कर दिया। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रगीत का दूसरा अंतरा शुरू होते ही सोनिया गांधी असहज दिखाई दीं और वीडियो में उन्हें ‘स्टॉप-स्टॉप’ कहते सुना जा सकता है। हालांकि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत रोकने के आरोप से इन्कार किया है। शर्मा ने कहा कि जनता पूरा घटनाक्रम देख रही है और वह इसका जवाब देगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पंजाब में सक्रियता से जुड़े सवाल पर रेखा शर्मा ने कहा कि भाजपा में प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन की ओर से दी गई जिम्मेदारी निभानी होती है

भाजपा ने सौदान सिंह को फिर दी चंडीगढ़ की कमान, राष्ट्रीय सहमहामंत्री की भी जिम्मेदारी

समर न्यूज़ | चंडीगढ़

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने सोमवार को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई नियुक्तियों की सूची जारी की। इसमें चंडीगढ़ की संगठनात्मक जिम्मेदारी संभाल रहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह के दायित्व में बदलाव किया गया है। सौदान सिंह अब राष्ट्रीय सहमहामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। हालांकि चंडीगढ़ का संगठनात्मक कामकाज पहले की तरह उनके पास ही रहेगा। नई जिम्मेदारी के साथ वह संगठन से जुड़े निर्णयों को पहले के मुकाबले अधिक प्रभावी तरीके से ले सकेंगे।

दिल्ली में जल्द शुरू होगा ई-कैबिनेट सिस्टम

■ कैबिनेट नोट से लेकर फैसलों और बैठक की कार्यवाही तक सब कुछ डिजिटल होगा

एजेंसी | नई दिल्ली

दिल्ली सरकार जल्द ही ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने जा रही है। इसके बाद मंत्रिमंडल की बैठकों से जुड़ी पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जा सकेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों के साथ इस संबंध में विस्तृत चर्चा की है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से कैबिनेट की कार्यवाही कागजरहित, सुरक्षित, तेज और अधिक पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

ई-कैबिनेट के तहत मंत्रिमंडल के सामने रखे जाने वाले प्रस्तावों से लेकर उनके अनुमोदन और संबंधित विभागों को फैसले भेजने तक की प्रक्रिया डिजिटल होगी। इससे फाइलों के भौतिक आवागमन में कमी आएगी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बेहतर होने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य केवल कागज की बचत करना नहीं, बल्कि निर्णय



डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल की व्यवस्था की जाएगी।

इससे किसी प्रस्ताव पर निर्णय के लिए फाइल को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक पहुंचाने में लगने वाला समय कम हो सकता है। अधिकारियों के अनुसार डिजिटल प्रणाली में प्रस्ताव की स्थिति को ट्रैक करना भी आसान होगा। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि कोई प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित है और मंजूरी के बाद कितना काम किया है।

■ गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा पर

जोर: कैबिनेट से जुड़े कई दस्तावेज संवेदनशील और गोपनीय होते हैं। इसलिए प्रस्तावित व्यवस्था में हर मंत्री और अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी के अनुसार अलग-अलग स्तर की डिजिटल पहुंच देने की योजना है। साइबर सुरक्षा उपायों, डेटा एन्क्रिप्शन और नियंत्रित पहुंच के जरिए गोपनीय जानकारी को अनधिकृत लोगों तक पहुंचने से रोकने पर जोर रहेगा।

इस व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी होगा कि सभी दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित तरीके से रखा जा सकेगा। इससे पुराने कैबिनेट फैसलों और उनसे जुड़े दस्तावेजों को जरूरत पड़ने पर खोजना आसान होगा। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस से जुड़े दस्तावेजों में भी ई-कैबिनेट को कागजरहित व्यवस्था, डिजिटल दस्तावेज प्रवाह और पुराने फैसलों के रिकॉर्ड तक आसान पहुंच देने वाली प्रणाली के रूप में बताया है।

■ फैसलों के अमल की भी होगी निगरानी: नई प्रणाली का

फायदा केवल कैबिनेट बैठक तक सीमित रखने की योजना नहीं है। सरकार चाहती है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन की स्थिति पर भी नजर रखी जा सके। डिजिटल व्यवस्था में संबंधित विभागों को फैसले भेजने और अनुपालन की प्रगति की निगरानी का प्रावधान होगा।

दिल्ली से पहले कई राज्यों में प्रयोग: ई-कैबिनेट की अवधारणा देश के कई राज्यों में पहले से इस्तेमाल हो रही है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के एक दस्तावेज के अनुसार उत्तराखंड में ई-कैबिनेट प्रणाली जनवरी 2020 में शुरू की गई थी और बाद में उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में भी इसे अपनाया गया। दिल्ली में भी इस प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने दिल्ली सरकार को दूसरे राज्यों में लागू डिजिटल कैबिनेट प्रणालियों और उनके अनुभवों की जानकारी दी है।

जमीन की रजिस्ट्री में स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण मान्य मकानों के हस्तांतरण दस्तावेजों पर स्टॉप ड्यूटी में कटौती

हरियाणा सरकार ने जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों में पहचान की प्रक्रिया को किया आसान

समर न्यूज़ | पंचकूला

हरियाणा सरकार ने जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों में पहचान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए खरीदार, विक्रेता और गवाहों को स्वैच्छिक रूप से आधार के माध्यम से पहचान सत्यापित कराने की सुविधा दी है। वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत 60 वर्ग मीटर तक के मकानों के संपत्ति हस्तांतरण दस्तावेजों पर स्टॉप ड्यूटी घटाकर महज 500 रुपए कर दी गई है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दोनों फैसले हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। आधार प्रमाणीकरण से संबंधित अधिसूचना के अनुसार हरियाणा में किसी भी भूखंड की बिक्री एवं खरीद के दौरान खरीदार, विक्रेता और गवाह की पहचान की पुष्टि आधार के बिना

ई-केवाईसी सुविधा के माध्यम से की जा सकेगी। हालांकि, यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वैच्छिक होगी और आधार संख्या धारक की सहमति से ही प्रमाणीकरण किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा आधार प्रमाणीकरण कराने से इनकार करने अथवा ऐसा करने में असमर्थ रहने पर उसे किसी भी सेवा से वंचित नहीं किया जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति को पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक और व्यवहार्य माध्यम उपलब्ध कराने होंगे।

यह निर्णय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुमति के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से परामर्श के बाद हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दी है। दूसरे महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने 60 वर्ग मीटर तक के

मकानों के कन्वेयंस डीड पर स्टॉप ड्यूटी 500 रुपए निर्धारित की है। 10 अगस्त को जारी आदेश भारतीय स्टॉप अधिनियम, 1899 की धारा 9 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किया गया है। यह दर अधिनियम की अनुसूची 1-ए के अनुच्छेद 23(ए) के तहत लागू होगी। हालांकि, 500 रुपए की स्टॉप ड्यूटी की सुविधा 60 वर्ग मीटर तक के सभी मकानों पर लागू नहीं होगी।

इसका लाभ केवल उन्हीं मकानों के हस्तांतरण पर मिलेगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत हैं और जिनके खरीदार अथवा हस्तांतरित व्यक्ति को योजना का पंजीकृत लाभार्थी होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए आवास सभी के लिए विभाग अथवा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी की ओर से जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मेयर विदेश गईं, अब कुछ दिन कौन संभालेगा लुधियाना निगम की कामान?

लवकी मेहता | लुधियाना

समर न्यूज़

लुधियाना नगर निगम की मेयर इंटरजित कौर विदेशी दौर पर गई हैं। सूत्रों के अनुसार मेयर का यह दौरा करीब 8 से 15 दिन का हो सकता है। मेयर के शहर से बाहर रहने के दौरान अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन दिनों नगर निगम की राजनीतिक कामान कौन संभालेगा।

उनकी गैरमौजूदगी को लेकर निगम के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। नगर निगम में मेयर का पद कई महत्वपूर्ण बैठकों और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा होता है। ऐसे में मेयर के विदेश दौर पर जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी माना जा रहा है।

■ एक्ट में गैरहाजिरी की स्थिति का प्रावधान: नगर निगम एक्ट



1976 के सेक्शन 40(2) में मेयर की गैरमौजूदगी को लेकर प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक यदि मेयर बीमारी या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित रहते हैं तो उनकी गैरमौजूदगी में सीनियर डिप्टी मेयर के कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। वहीं, सीनियर डिप्टी मेयर की गैरमौजूदगी में डिप्टी मेयर यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ऐसे में मेयर के 8 से 15 दिन के संभावित विदेशी दौर के दौरान एकट के प्रावधान के मुताबिक निगम की राजनीतिक जिम्मेदारी सीनियर डिप्टी मेयर के पास रहने की संभावना है।

पार्षद निवत्कू भारती ने स्वतंत्रता दिवस मनाया



नीलकमल मोनू | लुधियाना

समर न्यूज़

वार्ड नंबर 30 में पार्षद निवत्कू भारती की ओर से स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व उत्सव और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उन्होंने देश की

आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले महान शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्षद निवत्कू भारती ने क्षेत्रवासियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और साधियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी से देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की।

श्री शिव पुराण कथा के आयोजन पर एसएस खुराना ने श्रद्धालुओं का जताया आभार

लवकी भट्टी | लुधियाना

समर न्यूज़

सिविल लाइंस स्थित श्री दंडी स्वामी तपोवन तपोभूमि आश्रम में अंसल

एस्टेट के एस.एस. खुराना की ओर से आयोजित सात दिवसीय श्री शिव पुराण कथा का भक्तिभाव के साथ समापन हुआ। हरिद्वार से पथारे कथा व्यास आचार्य श्री हरिकृष्ण जी महाराज

भाई मंझ सेवा जत्ये का कीर्तन समागम



नीलकमल मोनू | लुधियाना

समर न्यूज़

गुरुद्वारा दुख भंजन साहिब (शहीदों), फ्रेड्स कॉलोनी, बसंत सिटी, लुधियाना में भाई मंझ सेवा जत्ये का मॉडल ग्राम की ओर से लड़ीवार कीर्तन समागम एवं सिमरन अभ्यास कार्यक्रम करवाया गया।

भाई मंझ सेवा जत्ये का कीर्तन समागम

ने सातों दिनों तक भगवान शिव की महिमा, शिव पुराण के आध्यात्मिक महत्व और भगवान शिव की भक्ति से जुड़े प्रसंगों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया।



पंजाब यूनिवर्सिटी में दूषित पेयजल के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, प्रशासन को दिया अल्टीमेटम

शगुन कश्यप | चंडीगढ़

समर न्यूज़

पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रावासों और विभिन्न विभागों में कथित रूप से दूषित पेयजल मिलने के विरोध में एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (एसएसपी) से जुड़े विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। छात्र प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में करीब 18 हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान उनकी टीम ने छात्रावासों और विभागों में लगे पानी के टैंकों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई टैंक गंदे मिले और कुछ टैंकों में मिट्टी तथा काई जमा होने का दावा किया गया। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने आरोप लगाया कि कुलपति और प्रशासनिक कार्यालयों के पानी के टैंक साफ हैं, जबकि छात्रावासों तथा विभागों में

छात्रों का आरोप: शिकायतों पर नहीं हुई कारवाई



संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले कई दिनों से प्रशासन को शिकायतें और संबंधित वीडियो भेजे जा रहे थे, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विद्यार्थियों ने प्रशासन को अगले दिन तक पानी के टैंकों की सफाई शुरू करवाने का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं होने पर डीन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन तेज किया जाएगा।

छात्र प्रतिनिधियों के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर के साथ बातचीत हुई है। बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि प्रत्येक छात्रावास से दो विद्यार्थी, वार्डन और सफाई टीम के साथ मिलकर हर 15 दिन बाद पानी के टैंकों तथा वाटर कूलरो का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद हस्ताक्षरयुक्त रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। विद्यार्थियों ने कहा कि यदि प्रशासन निर्धारित समय में औपचारिक अटेंडेंस जारी कर सफाई अभियान शुरू करता है तो यह छात्रों की सामूहिक आवाज की जीत होगी। फिलहाल विवेचिवालय प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों का दूसरा घर होता है और वहां स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने परिसर

संविदा कर्मियों के सुपरन्यूमेरी पदों के सृजन प्रस्तावों की प्रक्रिया हुई ऑनलाइन

समर न्यूज़ | पंचकूला

हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ देने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि पात्र संविदा कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमेरी पद सृजित कर संबंधी प्रस्ताव अब केवल निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही भेजे जाएंगे।

इन प्रस्तावों के लिए भौतिक फाइलें स्वीकार नहीं की जाएंगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य प्रशासकों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को पत्र जारी किया है। विभाग ने कहा कि यह व्यवस्था हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 और इसके तहत बनाए गए नियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप की गई है।

निशुल्क मेडिकल कैंप में 340 मरीजों की जांच, दवाइयां बांटी



लवकी मेहता | लुधियाना

समर न्यूज़

राजपूत समाज एकता मंच की ओर से स्वतंत्रता दिवस को समर्पित निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन गियासपुरा स्थित राजीव गांधी कंप्यूटर सेंटर में किया गया।

कैंप का उद्घाटन अखिल भारतीय शक्ति महासभा के अध्यक्ष एवं मुख्य अतिथि डिंपल राणा ने ध्वजारोहण कर किया। कैंप में 340 मरीजों की जांच कर उन्हें निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। इस दौरान दांतों, आंखों और सामान्य बीमारियों की जांच के

साथ ईसीजी, बीपी और शुगर की जांच भी की गई। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। डिंपल राणा ने कहा कि शहीदों की कुर्बानियों से मिली आजादी अमूल्य है।

देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखते हुए संविधान में मिले अधिकारों का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने कैंप के आयोजन के लिए मंच के अध्यक्ष लक्वी राजपूत और उनकी टीम की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सहयोगियों को स्मृति चिन्ह देकर समाप्तित किया गया और लोगों में लड्डू वितरित किए गए।

मोहाली ट्रैकिंग क्लब ने गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब परिसर में लगाए पौधे



गुरशरण | मोहाली

समर न्यूज़

मोहाली ट्रैकिंग क्लब की ओर से पौधों के को-कन्वीनर अजय भारती ने किया। उन्होंने कहा कि सफल उद्यमियों के अनुभव नए उद्यमियों को आत्मविश्वास और स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं। पीएचडीसीसीआई पंजाब चैप्टर के सह-संयोजक सीए विशाल गर्ग ने अतिथियों का आभार जताया। कार्यक्रम में बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र, अमृतसर की ओर से आईपीआर संबंधी जानकारी देने के लिए डेस्क भी लगाया गया।

पौधरोपण बेहद जरूरी है और सभी लोगों को अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक सागर सिंह, हरनक सिंह, भगती सिंह, सतनाम सिंह सहित अन्य सेवादार मौजूद रहे।

इसके अलावा मोहाली ट्रैकिंग क्लब के चेयरमैन नवजोत सिंह बाखल, सीनियर वाइस चेयरमैन प्रमोद मिश्रा, उपाध्यक्ष मनमोहन सिंह, सलाहकार राजिंदर सिंह, प्रचार सचिव गुप्ती सिंह सियाण तथा क्लब के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे।



सौरभ मुंजाल ने कहा कि उद्यमी के सफर में अवसरों के साथ चुनौतियां और कठिन फैसले भी आते हैं। बाजार की जरूरतों को समझते हुए जोखिम उठाने, जरूरत पड़ने पर रणनीति बदलने और लगातार आगे बढ़ने की क्षमता सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने उपभोक्ता-केंद्रित कारोबार तैयार करने और उसे विस्तार देने के अनुभव भी साझा किए। सीआईसीपी मटेरिअल हनी सेठी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम उद्यमिता की सोच और ज्ञान के आदान-

प्रदान को बढ़ावा देते हैं। सत्र का संचालन पीएचडीसीसीआई के लुधियाना जोन के को-कन्वीनर अजय भारती ने किया। उन्होंने कहा कि सफल उद्यमियों के अनुभव नए उद्यमियों को आत्मविश्वास और स्पष्टता प्रदान कर सकते हैं। पीएचडीसीसीआई पंजाब चैप्टर के सह-संयोजक सीए विशाल गर्ग ने अतिथियों का आभार जताया। कार्यक्रम में बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र, अमृतसर की ओर से आईपीआर संबंधी जानकारी देने के लिए डेस्क भी लगाया गया।

पब्लिक की बैठने की जगह पर निजी कामकाज! सरकारी बिजली के इस्तेमाल पर भी उठे सवाल

राजवीर बखशी | लुधियाना

समर न्यूज़

लुधियाना के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पूर्वी रजिस्ट्रार कार्यालय में पब्लिक की सुविधा के लिए बनाई गई बैठने की जगह को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि यहां एक निजी व्यक्ति पब्लिक के बैठने के लिए निर्धारित स्थान पर बैठकर अपना निजी कामकाज करता नजर आया। मौके पर उक्त व्यक्ति लैपटॉप पर काम करता दिखाई दिया, जबकि उसके पास पंखा और प्रिंटर भी लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि प्रिंटर से पासपोर्ट साइज फोटो भी निकाली जा रही थीं। ऐसे में सवाल

उठ रहा है कि सरकारी कार्यालय में पब्लिक के लिए निर्धारित जगह पर निजी कामकाज करने की अनुमति आखिर किसने दी?

■ सरकारी बिजली से निजी काम?... मामले में सबसे गंभीर सवाल सरकारी बिजली के इस्तेमाल को लेकर उठ रहा है। यदि मौके पर चल रहा पंखा और प्रिंटर रजिस्ट्रार कार्यालय की बिजली से संचालित हो रहे थे, तो निजी काम के लिए सरकारी बिजली का इस्तेमाल किसकी अनुमति से किया जा रहा था? इसकी जांच होना जरूरी है।

■ जगह मिली तो किस आधार पर?... पब्लिक की ओर से यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि यदि किसी निजी व्यक्ति को कार्यालय परिसर में बैठकर काम करने की अनुमति दी गई है तो क्या इसके लिए कोई लिखित आदेश, अलॉटमेंट या किराया निर्धारित किया गया है? या फिर बिना किसी आधिकारिक अनुमति के ही पब्लिक की जगह पर निजी कामकाज चल रहा है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि रजिस्ट्रार कार्यालय में रोजाना बड़ी संख्या में लोग अपनी संपत्तियों की रजिस्ट्री करवाने पहुंचते हैं। ऐसे में पब्लिक के लिए निर्धारित स्थान का निजी इस्तेमाल होने से कार्यालय की व्यवस्था और

पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ■ एडीसी ने कहा- मामला ध्यान में नहीं, अभी करवाती हूं चेक... मामले को लेकर जब एडीसी शिखा भगत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके ध्यान में नहीं है। उन्होंने कहा कि वह इसकी जांच करवाएंगी।

अब देखना होगा कि जांच के दौरान मौके पर निजी व्यक्ति के कामकाज और सरकारी बिजली के इस्तेमाल को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं और यदि बिना अनुमति के सरकारी जगह या बिजली का इस्तेमाल पाया जाता है तो संबंधित विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है।

